लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1677

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिला-आधारित वस्त्र रूपांतरण

1677. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जुगल किशोर:
श्री नव चरण माझी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला-आधारित प्रौद्योगिकी रूपांतरण (डीएलटीटी) के अंतर्गत जिला-वार दृष्टिकोण अपनाने का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो डेटा-आधारित स्कोरिंग प्रणाली किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि पारंपरिक और आदिवासी शिल्प समूह और छोटे उत्पादन समूह ओडिशा के नबरंगपुर और आंध्र प्रदेश के बापतला जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों से पिछड़ न जाएं;

(ग) उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों और मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटरों के साथ 100 उच्च क्षमता वाले अग्रणी जिलों का उन्नयन करने की समय-सीमा क्या है और क्या नबरंगपुर जिले को इसमें शामिल किया गया है; और

(घ) ओडिशा के नबरंगपुर, राजस्थान के भीम और कुंभलगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के बापतला सहित पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जीआई-टैग वाले जनजातीय हस्तशिल्पों को डीएलटीटी ढांचे के माध्यम से अग्रणी वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूर्वोदय योजना के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): जी हाँ, जिला आधारित टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन (DLTT) का एक मुख्य उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता को दूर करके संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 777 जिलों का मूल्यांकन एक वेटेड स्कोरिंग मॉडल (0-100) के आधार पर किया गया, जिसमें तीन संकेतकों अर्थात् टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात, उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत वस्त्र और अपैरल इकाइयों की संख्या, और ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का प्रयोग है। इसका निष्पादन योजनाबद्ध रूप से तीन चरणों में है 1) एक्सपोजर विजिट 2) लक्षित इंटरवेंशन और 3) मूल्यांकन और डॉक्यूमेंटेशन।

(घ): DLTT के तहत पूर्वोदय कन्वर्जेंस का उद्देश्य देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जिलों में क्षेत्रीय असमानताओं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं आदि को दूर करना है, विशेष रूप से इसका कवरेज पूर्वी (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) और पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा) राज्यों में है।

***